एलीमेंट इस देश का पूंजीपति है वह सारी अर्थ व्यवस्था पर हावी है और जो छोटी छोटी यूनिट के लोग हैं जो कि पैसा लेना चाहते हैं इनवेस्टमेंट करने के लिये, और इंडस्ट्री खड़ी करने के लिये, स्माल स्केल इंटस्ट्री की स्थापना के लिये जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अगर बिरला जी जायें, झनझनिया जी जायें, चनचनिया जी जायें, मोरारका-जी जायें, डालमिया जी जायें तो उन्हें जल्द से जल्द कर्ज मिल जायेगा। लेकिन स्माल यूनिट्स के लिये मिलने में दिक्कत होगी। चाहे मोरारजी भाई हो या कोई और यह बात देखी गई है। इसलिये मै आपसे कहूंगा कि... (Interruptions)

आप वैसे ही सिस्टम के रहने वाले हैं

5 P.M. और वही कर रहे हैं। लेकिन आप के यहाँ क्या हुआ? आपने गोयनका साहब को जो फायदा अपने राज में पहुंचाया उसको आडवाणी जी आप मत भूलें। आपने सत्ता में आते ही गोयनका साहब को फायदा पहुंचाया। यह बात छिपी नहीं है (Interruptions) करोड़ो रुपया हिन्दुस्तान लीवर को आपने फायदा पहुंचाया। आपने जितना फायदा पहुंचाया वह छिपा नहीं है। अगर आप कहलवाना चाहते हैं तो मै एक एक करके कह सकता हूं। तो मैं यह कह रहा था कि सिक यूनिट को अगर गवर्नमेंट लेती है तो वापिस न लोटाया जाए।

The sick indusries should not be returned after they have been restored to health by investing such a huge amount by the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. GULKARNI): It is already 5 P.M. I think this debate will now be carried over.

SHRI RAMANAND YADAV: I will be continuing my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): There are now two items. One is the continuation of the discussion on the Calling Attention Motion. It is a very rare occasion in this House that it is taken up after 5 P.M. Anyway, Shri J. P. Mathur will start. Please be very brief. You are at the fag-end of the day.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The situation arising out of the recent increase in the prices of petrol, diesel, kerosene, fertilizers and other petroleum products—contd.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रातःकाल मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए दो बातें ऐसी कह दीं जो मै नहीं समझता हूं कि सोच कर कही गई हैं अथवा वे जल्दी में कह गए हैं। एक बात तो उन्होंने यह कही कि तेल की जितनी कीमतें धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी इन सारी कीमतों का भार धीरे धीरे बराबर कन्ज्यूमर पर डलता चला जाएगा, जमीन की कीमतें बढ़ाते चले जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने यह कह दी कि हम किसान को सुविधा देने की दृष्टि से जो गेहूं की परचेज प्राइस है उसको बढ़ा देंगे। इन चीजों में मैं विस्तार में नहीं जाएंगा। उनके पहले स्टेटमेंट से बाजार पर असर पड़ेगा और पेट्रोल की चोरी प्रारम्भ हो सकती है। जब उनका कहना यह है कि कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी तो चोरी शुरु हो जाएगी। ऐसे ही गेहूं का है। उन्होंने यह कहा कि प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा देंगे। मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय ने यह वक्तव्य कृषि मंत्रालय से पूछ कर दिया है या नहीं। अथवा एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से पूछ कर दिया है या नहीं। मैं नहीं जानता कि पूछ कर दिया है या नहीं लेकिन इस का परिणाम क्या होगा? किसान

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

को जो सुविधा मिलती है वह मिलेगी या नहीं परन्तु बाजार में अभी से कीमतें चढ़ना शुरू हो जाएंगी। जिम्मेदारी की दो बातें उन्होंने कैसे कह दी हैं, यह मैं नहीं कह सकता। जैसे उन्होंने कहा पेट्रोल की कीमतें बाजार में बढ़ती चली जाएगी। तो क्या उनका विचार किसी प्रकार से राशन करने का है? अगर वे राशन करना चाहते हैं तो इसकी घोषणा वे कब करना चाहते हैं? दूसरे प्रश्न मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। वे मेरे साथियों ने कह दिए हैं। किसानों को 25 से 33 प्रतिशत तक सबसिडी देने की बात कही गई है। 25 या 33 प्रतिशत अगर आप छूट किसानों को दे भी दें मगर सारी कीमतें जो बढ़ेंगी तो किसान पर तो भार उस का पड़ेगा इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों के लिए कम से कम प्राइस आप फिक्स कर दें। जिससे ज्यादा कीमत पर किसान को नहीं दिया जाएगा। अब मैं आता हूं कीमतों पर। मेरे पास एक जानकारी है। पिछले महीने जब आप मंत्री जी नहीं थे दो अन्तर्राष्ट्रीय कंट्रेक्टर्ज से सौदा किया गया कि वे पाँच लाख और तीन लाख टन डीजल और केरोसीन देंगे। उनकी कीमत 380 डालर से ले कर 390 डालर प्रति टन कोट की गई। लेकिन बीच में कोई अड़चन आ गई। मंत्री महोदय ने अधिकारियों को बुलाया और यह कहा कि एक और कंट्रेक्टर जो 350 रुपये प्रति टन के हिसाब से तेल देने को तैयार है और भाड़ा जोड़ने पर 409 डालर के हिसाब से तेल देने को तैयार है। अफसरों ने इस पर एतराज किया और कहा कि यह कैसे हो सकता है। पहला जो कान्ट्रेक्ट है वह लांग टर्म कान्ट्रेक्ट है उसमें कीमतों का बढ़ाव और घटाव भी एक क्लाज है। स्माल टर्म कन्ट्रेक्ट के अंदर यह क्लाज नहीं होता है। अधिकारियों ने यह सलाह दी कि यह छोटे टर्म का कान्ट्रेक्ट नहीं होना चाहिए दूसरा यह गैर जिम्मेदार व्यापारी है तो इसको हम ठेका कैसे दे सकते हैं। तब उनको यह कहा गया कि 409–350 टन के हिसाब से फ्रेट भी शामिल करना ठेकदार स्वीकार कर लेगा। जो चिंताजनक बात है वह यह है कि जब यह बात कही गयी मंत्री महोदय की तरफ से अफसरों को कि वे फ्रेट भी शामिल करेंगे तो प्रश्न उठा कि इतना सस्ता वह ठेकेदार कैसे देगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह 380–390 डालर टन की कीमतों के जो टेंडर आये थे ये खुल कैसे गये, तीसरे ठेकेदार को किसने यह बताया। मुझे जानकारी है कि यह मामला कैसे खोला गया?

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। इस समय दो नाम के बाजार के अंदर घूम रहे हैं। एक है कोई हाडू चंद जी जैन जो इसमें बीच में पता नहीं कहां से आ गये और इसमें पेग्राफ लेना चाहते थे। दूसरे मैं नहीं जानता हूं कि कौन सज्जन हैं शायद आपने उल्लेख किया था, श्रीमन्, जब आप वहां बोल रहे थे, कोई संसद सदस्य थे मध्य प्रदेश के. . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A G. KULKARNI): I cannot express any opinion while sitting here. You can express your opinion.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आपको याद दिला रहा हूं? अच्छा श्रीमन्, आपने नहीं मिस्टर कुलकर्णी ने नाम लिया था। मध्य प्रदेश के एक सदस्य का नाम लिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी जांच करेंगे। जो मैंने कीमतें बतायी हैं, दो कम्पनियों के कान्ट्रेक्ट

बतायें हैं और तीसरा ठेकेदार बीच में आया था तथा जिस बात पर अफसरों ने एतराज किया था, यह कान्ट्रेक्ट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ? अभी खत्म हुआ है या पेंडिंग है ? दूसरा इस समय हमारे लांग टर्म कान्ट्रेक्ट किन किन देशों में हैं और कब कब खत्म होने वाले हैं तथा नये कान्ट्रेक्ट कहां करने वाले हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल . मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है माननीय सदस्य ने उसमें आपत्ति की है । मैं ने कहा था कि आयल प्राइसेज जो आज हैं आइंदा भी वहां रहेंगे यह कहा नहीं जा सकता है क्योंकि मेरे स्टेटमेंट देने के बाद ही दो डालर बढ़ गये हैं । मैंने कहा था कि जैसे भी तेल के भाव बढ़ेंगे तो तेल जो कन्जूम करते हैं उनको यह बर्डेन लेना चाहिए । यह मैंने कोई नया स्टेटमेंट नहीं दिया है बल्कि जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर किया और मेरे कुलीग ने किया था तथा लोअर हाउस में मैंने कहा था तो उसमें मैं साफ तौर पर बता दिया था वह मैं एक्सट्रेक्ट पढ़ना चाहता हूं :

"If and when there is no knowing what escalations will be take place in future, if and when they do take place, there is no way we can sustain viability of the oil industry except by passing on the burden to the consumer to the extent unavoidably necessary."

तो मैंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी अनएवाईडेबुल हो जाता है उतना बर्डेन तो हमको पास आन करना पड़ेगा क्योंकि उसको हम एबजार्ब नहीं कर सकते हैं । यह मैंने कहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो मैंने कहा है ठीक कहा है । दूसरी बात उन्होंने मुझसे पूछी कि व्हीट का परचेज प्राईस बढ़ाने के ताल्लुक में मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है । तो इसका तो मैंने नाम हीं नहीं लिया, इंग्लिश में मैंने कहा था :

"The Government have also decided that the increase in the prices of fertilizers would be taken into account in recommending support or procurement price for crops beginning kharif 1980 so as to compensate the farmers in the price increases now affected."

यह मैंने कहा था कि जितना भी फर्टिलाईजर प्राइसेस में ज्यादा होता है उसको एकाउंट में लेकर किस तरह से उनको कम्पेंसेट करना चाहिए, उसके ताल्लुक से गवर्नमेंट सोच रही है यह मैंने कहा था । मैं समझता हूं कि मैंने जो कहा था वह गलत नहीं है ।

अब टेंडर के बारे में आपने जिक्र किया । कई टेंडर हैं मुझे मालूम नहीं है वे तफसीलात मेरे पास नहीं हैं । मैं उस टेंडर के बारे में जो आपका स्टेटमेंट है, कुछ नाम वगैरह का उन्होंने जिक्र किया है, उसका एक्सट्रेक्ट ले लूंगा और देखूंगा कि उसमें क्या हुआ है, क्या इररेग्यूलरिटीज हुई हैं या नहीं हुई हैं । मैं आज कुछ कहने की हालत में नहीं हूं । इतना मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं । अब किस किस देश से हम ले रहे हैं, यह तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह तो पब्लिक इंट्रस्ट में नहीं है । लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जितना क्रूड आयल हम ले रहे हैं, वह दूसरी गवर्नमेंट, कंट्रीज से हम ले रहे हैं, प्राइवेट पार्टी से हम क्रूड आयल नहीं लेते हैं । क्रूड आयल जो हम लेते हैं, दूसरी कंट्री से लेते हैं, यह गवर्नमेंट टु गवर्नमैंट एग्रीमैंट होता है ? जो पट्रोलियम प्राडक्टस हैं, पैट्रोलियम प्रोडक्टस हर साल लेते आ रहे हैं । अब की मर्तबा ज्यादा पट्रोलियम प्राडक्टस पर्चेज कर रहे हैं इसलिए कि जो असम में एजिटेशन चल रहा है, उसकी वजह से जो असम पांच मिलियन टन प्राडक्शन करता था, वह गुजिश्ता पांच महीने से बंद हो गया है । इसलिए हमको एक मिलियन टन ज्यादा स्पाट पर्चेज करना पड़ा । यह तो मार्केट में खरीदते हैं । जो सप्लाई करने वाला है,

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

वह कहां से लेकर सप्लाई करता है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन क्रूड आयल के ताल्लुक में कहूंगा कि क्रूड आयल गवर्नमैंट टु गवर्नमैंट लिया जाता है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं ने पूछा कि जब शार्टेज होगा, तो क्या पैंट्रोल का राशन करने का ख्याल है ?

श्री बीरेन्द्र पाटिल : पैंट्रोल की शार्टेज का सवाल नहीं है क्योंकि पैंट्रोल का कनजम्पशन पांच प्रतिशत आफ दी टोटल पट्रोलियम कनजम्शन है। इसलिए आप देखते होंगे कि कहीं भी पैंट्रोल का शार्टेज नहीं है। अगर कहीं एक-दो दिन का शार्टेज हो, तो मूवमैंट की कंस्ट्रेंट से होगा, दूसरी कोई वजह नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मंत्री महोदय ने अभी कहा, और बार-बार कहा है कि अनवाएडेबल हो गया, दूसरा कोई रास्ता नहीं है तेल के दाम को बढ़ाने के सिवा, क्योंकि इन्होंने जैसा भी कहा कि गवर्नमैंट टु गवर्नमैंट जहां कहीं से हम लेते हैं, हमको ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, इसीलिए इसकी कास्ट को बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब यह कि बोझ उपभोक्ताओं पर इन्होंने दे दिया। यह इन्होंने बार-बार कहा है कि मेरी मजबूरी है, मुझको करना पड़ा है। इस बोझ को कनज्यूमर पर पैंट्रोल और आयल के दाम बढ़ाने से क्लियर है कि जनता के जीवन-स्तर पर धक्का लगा है।

इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं कि जब साऊथ एवेन्यू से पार्लियामेंट आते थे एक रुपया आटो-रिक्शा में लगता था, जनता सरकार थी तो एक रुपया पच्चीस पैसे और अब एक रुपया सत्तर पैसे लगते हैं। साऊथ एवेन्यू से एक रुपया सत्तर पैसे आने और इतना ही जाने, तीन रुपया चालीस पैसे रोज लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आप तो एम० पी० हैं, आपको पैसे की कोई बात नहीं है। लेकिन यह धक्का तो उन लोगों को लगा है जो मिडल क्लास के हैं, विद्यार्थी लोग हैं, इन सबों के जीवन-स्तर पर इससे धक्का लगा है। अभी आपने कहा है कि अनएवाएडेबल था मैं थोड़ी देर के लिए माफ करता हूं, आपको चूंकि उधर कीमत ज्यादा देनी पड़ती है, तो कहीं से तो मेक-अप करना है। तो जनता पर आपने बढ़ाया है। लेकिन कुछ एवेन्यूज लाइनें हैं जहां आप जनता की राहत के लिए काम कर सकते हैं, जो आपके माध्यम की बात है। यह मेरा पहला सवाल है। जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आटो-रिक्शा से हमको एक रुपया सत्तर पैसे लगते हैं, लेकिन यह जो पार्लियामेंट की मिनि-बस है, उससे एक रुपया ही लगता है और हम देखते हैं कि वह मिनि-बस आती है कि नहीं, मिनि-बस से जाएंगे, आटो-रिक्शा से तो एक रुपया सत्तर पैसे लग जाते हैं। तो प्राइवेट पार्टी वाले, टैक्सी वाले, आटो-रिक्शा वालों को तो आप कह नहीं सकते हैं, मगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दिल्ली में या और दूसरी जगहों में हैं उनके फेयर्ज, टिकट की कीमत न बढ़े, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यह क्या आपके लिए संभव है ? तो आप कहेंगे कि खर्चा कहां से लेंगे। सब्सिडी ही समझें कि आप आम जनता के लिए, परिवहन के लिए आप लोग सब्सिडी ही दे रहे हैं बस फेयर में। जहां-जहां भी दिल्ली में या हिन्दुस्तान में जहां कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहीं भी फेयर न बढ़े जिससे कि विद्यार्थी समुदाय पर धक्का लगेगा और लोअर मिडल क्लास के लोगों पर धक्का लगेगा। फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले के बारे में भी आप यह कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत बोझ पड़ने से कुछ सब्सिडी के रूप में, दूसरे रूप में उसको मेक-अप करें। लेकिन बसेज के फेयर आप बढ़ने न दें।

दूसरी बात, आपने कहा फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं और विचार करेंगे कितना

देना चाहिए, खाद में और डीजल के रूप में। उस के लिए भी मैं कहता हूं यह बढ़ोत्तरी अगर उन लोगों पर होगी जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्माल फार्मर्स हैं, तो यह उचित नहीं होगा। ढाई एकड़ या तीन एकड़ वाले जो फार्मर्स हैं उनको कंट्रोल में निश्चित रूप से कम कीमत पर मिले, ऐसा भी आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं। डीजल के और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ने के बावजूद क्या आप एक मेजर सेक्टर को कंट्रोल प्राइस पर जो अभी तक है, क्या दे सकते हैं ? इसके लिए आप कोई नीति चला सकते हैं ?

तीसरा और आखरी सवाल मेरा है। आपको दूसरे देशों पर जहां तेल है डिपेन्डेन्ट होना पड़ता है, मुनहसिर होना पड़ता है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी भूमि में अभी तक पर्याप्त तेल नहीं है ? क्या पहाड़ की भूमि का आपने पूरा सरवे किया है ? क्या पूर्णिया जिला में रसौल का इलाका यह बहुत सारे इलाके हैं जहां तेल के खजाने हैं---ये बातें अखबार में आती रहती हैं और जब बहुगुणा जी मंत्री थे तब उन को भी कहा था क्या आपने पूरा सरवे करके वहां टैप करने का पूरा काम कर लिया है---हमें कहा गया कि उस काम को स्टेप-अप करेंगे और 10 वर्ष लग जाएंगे (Time bell rings) मैं मानता हूं। लेकिन आपका जो कंप्रिहेंसिव कदम है उस की शुरूआत तो हो जानी चाहिए। इसीलिए जितने अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं आइल के, उन को पूरी तरह एक्सप्लाइट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आप नेशनल लेवल पर स्कीम बनाएं ताकि हम को पता लग जाए कि 10 साल के बाद हम तेल के मामले में बिलकुल सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये मेरे 3 सवाल हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य ने मुझ से 3 सवाल पूछे हैं, एक तो यह कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेज वगैरह हैं, उन के फेयर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी ऐसा हम कर सकते हैं क्या ? तो यह कहना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि जब डीजल के प्राइसेज बढ़े हैं तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी फेयर प्राइस बढ़ेगा। अगर हम लोग कहेंगे कि प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए तो फिर वहां सब्सिडी देनी पड़ेगी और सब्सिडी कहां से देंगे, यह सवाल आ जाएगा। या तो डेफिशिट फाइनेंसिंग करना पड़ेगा या और तरह से टैक्स लेवी करना पड़ेगा क्योंकि जब भी डीजल का, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो आटो रिक्शास के फेयर बढ़े हैं, टैक्सीज के फेयर बढ़े हैं और बसों के फेयर बढ़े हैं। यह नया फीचर नहीं है। जो बस में ट्रैवल करना चाहते हैं उनको बढ़ा हुआ फेयर देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट सब्सिडाइज करने की हालत में नहीं है।

दूसरी बात, जहां तक फार्मर्स को कंट्रोल प्राइस पर देने की बात है, हमने तो प्राइस फिक्स कर दिया है, वह पुरानी प्राइस पर हम देंगे ही देंगे और हमने साफ तौर से स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया है कि जहां तक अग्रिकलचर सेक्टर का संबंध है, उसको टॉप प्रायरिटी देकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। वहां जो प्राइस हमने फिक्स कर दिया है उस प्राइस में मिलेगा, इतना मैं आश्वासन देना चाहता हूं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि डीजल का दाम और जगह बढ़ा लेकिन फार्मर के लिए एक और प्राइस कर सकते हैं। परंतु ड्यूअल प्राइस सिस्टम लागू करना बहुत कठिन काम है, मुश्किल काम है . . .

श्री शिव चन्द्र झा : मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनके लिए . . .

श्री वीरेन्द्र पाटिल : ड्यूअल प्राइसिंग नहीं हो सकता है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि हमने देश के अंदर तेल निकालने के लिए क्या प्रयत्न किया है ? मैं कहूंगा कि देश के अंदर तेल है, निकाल रहे हैं, अब 14 मिलियन टन हमारे देश के अंदर तेल

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

का प्रोडक्शन हो रहा है । हम तेल निकाल रहे हैं, हमारे देश के अंदर जो तेल है देश के अंदर ही रहेगा वह कहीं भाग कर नहीं जाएगा । इतना मैं कह देता हूं कि हम जितना तेल निकाल सकते हैं निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । हमारा जो आर्गेनाइजेशन ओ० एन० जी० जी० सी० है वह आन शोर और आफ शोर ड्रिलिंग के प्रोग्राम पर अमल कर रहा है । हमने उनसे और आगे प्रोग्राम बनाने के लिए कहा है और वह बना रहे हैं और उस के बाद हम कितना खर्च करेंगे कितनी ड्रिलिंग करेंगे, कितना ज्यादा तेल निकाल सकते हैं, वह सारा सरवें करने के बाद बतलाने की हालत में हम हो सकते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Now we shall take up Special Mentions.

REFERENCE TO THE ALLEGED BEATING OF SCHOOL CHILDREN BY CENTRAL POLICE INSIDE CIVIL HOSPITAL IN SHILLONG

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मेघालय की राजधानी शिलांग में वहां के अस्पताल में सेन्ट्रल पुलिस की तरफ से जो स्कूली बच्चों पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ है उस की ओर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । 5 जून को कुछ स्कूली लड़के अस्पताल में अपने साथियों को देखने के लिये गये हुए थे और अस्पताल के अन्दर ही सेन्ट्रल पुलिस ने उन के ऊपर लाठीचार्ज किया । मैं वहां के एक डाक्टर का कहना ही पढ़ कर सुना देना उचित समझता हूं :

According to a doctor, a patient undergoing eye treatment was accidentally beaten in the confusion.

यानी वद्यार्थियों को तो मारा ही, लेकिन जो बाकी के भी रोगी थे उन के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया जिस के कारण जबरदस्त आतंक का वातावरण वहां निर्माण हुआ है । यह घटना इसलिए हुई कि इस के पहले कुछ विद्यार्थियों ने वहां की स्टूडेन्ट यूनियन की तरफ से पुलिस की जबरदस्ती और दमनकारी नीति के विरुद्ध सत्याग्रह किया था । उस सत्याग्रह को पुलिस ने दबाने की दृष्टि से पहले भी लाठीचार्च किया था जिस में 50 लोग घायल हुए थे । उन घायलों को देखने के लिए लड़के गये हुए थे और उन के ऊपर इस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ । वहां के नेताओं ने जूडीशियल इनक्वायरी की मांग की थी, लेकिन कोई भी ऐसी इनक्वायरी वहां हो नहीं रही है, न इस प्रकार की कोई घोषणा की गयी है । इस सदन के माध्यम से सम्बन्धित मंत्री से यह मांग करता हूं कि वहां न्यायिक जांच करा कर जो भी इस दुर्घटना में घायल हुए हैं उन के लिए उचित चिकित्सा की व्यवस्था करें और उन की क्षतिपूर्ति करें ।

REFERENCE TO THE ALLEGED CRIMINAL ASSAULT BY A DELHI POLICE CONSTABLE ON A HOUSE WIFE IN J. P. HOSPITAL, NEW DELHI

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिए इस सदन के माध्यम से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर, जो जे० पी० हस्पताल में हुई, जिस में एक कांस्टेबिल ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, रेप किया, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जो अखबार में आया है वही मैं आप को सुना देना चाहता हूं । सब अखबारों में यह बात है । हिन्दी के अखबारों में बड़ी हैडलाइन में है । अंग्रेजी में भी है । मेरे पास आज का इन्डियन एक्सप्रैस है—

"A Delhi Police constable, Balbir Singh, was suspended and placed under arrest for allegedly raping a 22-year old woman on the lawns of J.P. Hospital early this morning."